Auction/closing down of non-viable units

1427. SHRI DIPEN GHOSH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to close down non-viable units in the public sector or to auction them off;

(b) if so, what are the details of th© said decision;

(c) the programme to rehabilitate the workers involved in those units;

(d) the plan to identify the persons responsible for the sickness of these non-viable units; and

(e) if there is no such plan to identify those persons, the reasons for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) At present there is no decision to close down non-viable units in the public sector undertakings or aution them off.

(b) and (c) Do not arise.

(d) and (e) The Government is constantly reviewing the various aspects of management of public enterprises includ* ing change in personnel, structure of the organisation etc. wherever neeessary with a view to improving their performance.

हिन्दी में कानून की पुस्तकों का प्रकाशन

1428. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या कानून से संबंधित पत्रिकाओं, संदर्भ ग्रन्थों और संदर्भ पत्रिकाओं तथा केश लॉ संबंधित पुस्तकों के हिन्दी पाठ इतने पर्याप्त नहीं हैं कि न्यायाधीश और अधिवक्ता इनका उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में प्रयोग कर सकें; और

(ख) क्या सरकार न्याय प्रणाली में राष्ट्र भाषा का प्रयोग करने का विचार रखती है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के उपयोग के लिए हिन्दी में पर्याप्त साहित्य उपलब्ध किए जाने के लिए निरन्तर प्रयत्न किए जा रहे हैं। सरकार प्रत्येक मास दो विधि पत्रिकाएं प्रकाशित करती है, जिनमें से एक में उच्चतम न्यायालय के निर्णय होते हैं और दूसरी में विभिन्न उच्च न्यायालयों के चुने हुए निर्णय होते हैं। सरकार हिन्दी में 19 मानक विधि पुस्तकें और एक विधि शब्दावली प्रकाशित कर चुकी है। प्राइवेट प्रकाशकों और लेखकों को पुरस्कार, आदि देकर हिन्दी में मूल प्रतियां प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सभी महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियम द्विभाषीय रूप में अर्थात्, अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित कर दिए गए हैं। हमारे लेखकों के लिए यह क्षेत्र नया है, अतः व्यापक रूप से साहित्य के सृजन में कुछ अधिक समय तो लगेगा ही और इसके लिए जनता साहित्यकारों। आदि द्वारा अथक प्रयत्न अपेक्षित होंगे। आपको यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि कुछ न्यायाधीश और अधिवक्तागण हिन्दी में उपलब्ध साहित्य का उपयोग कर रहे हैं और अपना कार्य हिन्दी में कर रहे हैं।

(ख) जी हां, संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अधीन जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियां निर्णय, आदि अंग्रेजी में ही होंगे। ऐसी कोई विधि अभी तक अधिनियमित नहीं की गई है। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 348(2) और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में या उसके द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों या किए जाने वाले आदेशों में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा के प्रयोग का प्राधिकार दे सकते हैं। अभी तक

चार उच्च न्यायालय अर्थात् , इलाहाबाद, पटना, राजस्थान और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों को अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में कार्यवाही करने और निर्णय देने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

Oil refinery in Assam

1429. SHRI SURA] PRASAD.
SHRl INDRADEEP SINHA:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Assam have 'opposed ihe opening of oil refinery in the private sector; and

(b) if so, what is the reaction of Central Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI NAWAL KISHORE SHARMA): (a) N_0 such objection has been received.

(b) Does not arise.

Drilling at Jogapatti

1430. SHRI SURAJ PRASAD:
SHRI INDRADEEP SINHA:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the drilling at Jo near Betiah (Bihar) has been slopped;

(b) whether it is also a fact that there is a possibility of getting crude oil there;

(c) whether it is also a fact that it has been found out in a survey that there is oil in the Gandak valley;

(d) if so, what are the $reason_s$ for stopping drilling; and

(e) whether Government propose to start drilling again?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI NAWAL KISHORE SHARMA): (a) to (e) On the basis of geo-scientific surveys conducted around Jogapatti near Betiah (Bihar), ONGC have drilled a well at Gandak. At present, the well is under testing. ONGC also propose to drill a well at Madhubani near Jaynagar, Darbanga District in Bihar.

देश में तेल शोधनशालाएं और पेट्रो-काम्पलेक्स

1431. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी तेल शोधन-शालायें हैं और वे कब से कार्य कर रहीं हैं;

(ख) उन पैट्रो-काम्पलेक्सों की संख्या कितनी है जिन्हें तेल शोधनशालाओं के चालू हो जाने के बाद स्थापित किया गया और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पैट्रो-काम्पलेक्सों की अब तक स्थापना नहीं की जा सकी और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पेट्रो-काम्पलेक्स की स्थापना के लिए आवश्यकतायें क्या हैं और पैट्रो-काम्पलेक्स की स्थापना से उस क्षेत्र के लोगों को क्या-क्या लाभ प्राप्त होते हैं ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) एक विवरण संलग्न है (नीचे देखिये)

(ख) और (ग) बड़ौदा, बम्बई और बोंगाईगांव में जहां शोधनशालाएं अवस्थित है, पेट्रोकेमिकल काम्पलेक्स की स्थापना की जाती हैं । जिन स्थानों पर शोधनशालाएं होती हैं, वहीं पर पेट्रो-रसायन परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक दृष्टिकोण से स्थापित किया जाता है । ऐसी परियोजनाओं की स्थापना से डाउन स्ट्रीम उपयोग हेतु कच्चे माल उपलब्ध होते हैं और उस क्षेत्र में रोजगार और औद्योगिकरण अवसर बढ़ते हैं ।